संख्या-194 /2016/1600/22-4-16-48(116)/15

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 21 दिसम्बर, 2016

विषय- प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से लगाये गये मोबाइल फोन जैमरों के सफल संचालन हेतु सोलर एनर्जी आधारित पावर बैकअप की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-42745/आधु0-01/मो0फो0जै0/2014, दिनांक-01 दिसम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्न तालिका में उल्लिखित कारागारों में लगाये गये मोबाइल फोन जैमरों के सफल संचालन हेतु सोलर एनर्जी आधारित पावर बैकअप की व्यवस्था हेतु रू0 3,51,00,000/- (रूपया तीन करोड़ इक्वान लाख मात्र) की लागत पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 3,35,32,000/-(रूपया तीन करोड़ पैंतीस लाख बत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	कारागार का नाम	जैमरों की सं0	सोलर पावर बैकअप की क्षमता (किलोवाट)	लागत प्रति किलोवाट	कुल लागत	ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित सब्सिडी	सब्सिडी के उपरान्त वास्तविक धनराशि/ स्वीकृत लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला कारागार मुजफ्फरनगर	6	15	2.34	35.10	5.85	29.25
2	के0का0 आगरा	6	15	2.34	35.10	5.85	29.25
3	जि0का0 वाराणसी	6	15	2.34	35.10	5.85	29.25
4	जि0का0 मिर्जापुर	8	20	2.34	46.80	7.80	39.00
5	जि0का सुल्तानुपर	9	22	2.34	58.50	9.75	48.75
6	जि0का0 मेरठ	15	40	2.34	93.60	15.60	78.00
7	जि0का गौतमबुध नगर	20	50	2.34	11.70	19.50	97.50
	योग-	70	155	13.80	421.20	70.20	351.00
							(रूपया तीन करोड़ इक्वान लाख मात्र)

(क) उक्त धनराशि का व्यय/ उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख) उक्त कार्य भारत सरकार के उघम पीईसी लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा एवं उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार उ0प्र0 एवं पीईसी लिमिटेड का होगा।

(ग) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(घ) सोलर एनर्जी आधारित पावर बैकअप उपकरणों को क्रय करते समय क्रय सम्बन्धी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा एवं किसी भी अनियमितता के लिए वह उत्तरदायी होंगे।

(ड़) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जायेगा।

(च) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता तथा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(छ) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग/व्यय उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

(ज) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिए जायं।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800- अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या- 194/2016/1600(1)/22-4-16-तददिनांकित-</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) प्रबंधक, पीईसी लिमिटेड " हंसालय" 15 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in